आज का मौसम

अधिकतम 35° C
न्यूनतम 20° C
सूर्य अस्त (आज) 6:11
सूर्य उदय (कल) 6:38

दैनिक समाचार पत्र

जीत समाचार

जीत सच्ची खबर की

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

अनमोल वचन

"आरंभ हो , अंत न हो मन इतना स्वतंत्र न हो सुख तोड़ा सा मिले कोई बात नही किंतु मन में कोई षड्यंत्र न हों।"

वर्ष : 13 | अंक : 192 | मूल्य : 2 रू | पृष्ठ : 8 | बुधवार 01 अप्रैल 2026 | RNI NO : PUNHIN/2013/60106 | www.zeetsamachar.com

संक्षिप्त न्यूज

देश में आज से लागू हुए कड़े 'ठोस कचरा बंधन नियम 2026' य चार अलग-अलग हिस्सों में कचरा बांटना हुआ अनिवार्य

राष्ट्रीय ब्यूरो, नई दिल्ली (31 मार्च)। देश में पर्यावरण और रीसाइक्लिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस कचरा प्रबंधन) नियम लागू कर दिए हैं, जिन्होंने 2016 के पुराने नियमों की जगह ली है। 31 मार्च को जारी अंतिम अधिसूचना के अनुसार, अब देश के हर नागरिक, हाउसिंग सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कचरे को चार श्रेणियों गीला , सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट (जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान या खतरनाक घरेलू कचरा) में अलग-अलग करके ही निगम की गाड़ियों को देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसायटियों और बड़े संस्थानों पर भारी पेनल्टी लगाने के साथ-साथ उद्योगों के लिए 'रिड्यूस डिराइव्ड फ्यूल' का इस्तेमाल 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ऐतिहासिक कामयाबी : बस्तर में 44 माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पणय

मुख्यमंत्री का बड़ा दावा 'नक्सलवाद के काले दौर से पूरी तरह मुक्त हुआ छत्तीसगढ़'

राष्ट्रीय ब्यूरो, रायपुर

रायपुर (31 मार्च)। देश के आंतरिक सुरक्षा मोर्चे से मंगलवार को एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक सफलता की खबर आई है। लाल आतंक के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पांच अलग-अलग जिलों के 44 सक्रिय माओवादियों ने एक साथ सुरक्षा बलों के सामने अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई ऐसे खूंखार चेहरे भी शामिल हैं, जिन पर सरकार ने लाखों रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इस अभूतपूर्व सफलता पर गहरी खुशी जताते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रेस कहन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया कि "सुरक्षाबलों के कड़े प्रहार और सरकार की नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से माओवाद (नक्सल) मुक्त होने की ऐतिहासिक दिशा में बढ़ चुका है।"

बस्तर के इन 5 जिलों में खौफ का पर्याय थे ये माओवादी : आईजी बस्तर रेंज और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस सामूहिक आत्मसमर्पण में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में सक्रिय नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले कमांडरों ने स्वीकार किया कि वे माओवादी संगठन की खोखली विचारधारा, आंतरिक शोषण और सुरक्षाबलों द्वारा लगातार जंगलों में चलाए जा रहे 'सर्च ऑपरेशन' से पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्होंने बस्तर के गांवों में हो रहे विकास, सड़कों के निर्माण और नए पुलिस कैंपों की स्थापना को देखकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा नया जीवन, आत्मसमर्पण करने वालों को तोहफे : राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी 44 पूर्व नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की नई 'लोन वर्राटू' (घर वापस आइए) और केंद्रीय पुनर्वास नीति के तहत तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इन सभी को पक्के मकान बनाने के लिए कृषि योग्य जमीनों के पट्टे, स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज का लोन और इनके बच्चों को सरकारी खर्च पर हॉस्टल व मुफ्त शिक्षा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि वे समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

सुरक्षाबलों का सख्त संदेश या तो रास्ता बदलो या फिर अंजाम भुगतो : इस मौके पर बस्तर के सुरक्षा प्रमुखों ने दोटूक शब्दों में कहा कि जंगलों में छिपे बाकी बचे मुट्ठी भर नक्सलियों के लिए भी यह एक खुला संदेश है। सरकार के दरवाजे उनके आत्मसमर्पण के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर वे हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तो सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन क्लीन' इसी तरह जारी रहेगा। इस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण के बाद पूरे बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ताकि बौखलाहट में नक्सली संगठन कोई कायराना हरकत न कर सकें।

इनामी कमांडरों की लिस्ट : "सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पीएलजीए कंपनी नंबर-2 का खूंखार मिलिट्री कमांडर (इनाम 8 लाख) और दो महिला एरिया कमेटी सदस्य (इनाम 5–5 लाख) शामिल हैं। इन सभी पर सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमला करने, बारूदी सुरंग ब्लास्ट करने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे।"

ऐतिहासिक मील का पत्थर: गृह मंत्रलय का बड़ा एलान

"लाल आतंक के खूनी दौर से पूरी तरह मुक्त हुआ भारत"

संवाद न्यूज एजेंसी

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली (31 मार्च)। भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में मंगलवार, 31 मार्च 2026 का दिन हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक तौर पर देश को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार की देर रात जारी एक विशेष प्रेस नोट और श्वेत-पत्र के अनुसार, सरकार ने देश को पूरी तरह से नक्सल-मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की जो अंतिम समय-सीमा तय की थी, उसे सुरक्षाबलों के कड़े, सुनियोजित और निरंतर अभियानों के जरिए समय पर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद देश के उन सुदूर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में जश्न का माहौल है, जो दशकों से हिंसा का दंश झेल रहे थे।

ठोस सुरक्षा ग्रिड नीति और चौतरफा विकास ने तोड़ी लाल आतंक की रीढ़ : गृह मंत्रालय के श्वेत-पत्र के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में अपनाई गई जीरो-टहलरेंस की नीति इस बड़ी सफलता का मुख्य आधार रही है। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए देश के सबसे संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में 663 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों और 408 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई। कोबरा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्थानीय पुलिस बलों के साझा अभियानों ने नक्सलियों की रसद, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया, जिससे उनके पास आत्मसमर्पण करने या पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

जंगलों तक पहुंची विकास की किरण, मुख्यधारा में लौटे भटके युवा : मंत्रालय ने साफ किया कि यह ऐतिहासिक कामयाबी सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि चौतरफा विकास के जरिए मिली है। 'लाल गलियारे' के नाम से कुख्यात रहे इलाकों में हजारों किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर पक्की सड़कों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की शुरुआत और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं ने स्थानीय युवाओं को नक्सलवाद के जाल से दूर रखा। इसके साथ ही, राज्य सरकारों की आकर्षक और सुरक्षित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियों के चलते पिछले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में कैडरों और बड़े कमांडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक मुख्यधारा को गले लगाया।

सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान को गृह मंत्रालय ने किया नमन : श्वेत-पत्र जारी करते हुए गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश की अखंडता और शांति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राज्य पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंत्रालय ने कहा कि वीर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया है और आज देश का जो भी हिस्सा विकास की नई इबारत लिख रहा है, वह इन्हीं जांबाजों की बदौलत है। अब इन मुक्त हुए क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और औद्योगिक विकास को तेज गति दी जाएगी।

आंकड़ों की जुबानी : दशक पुरानी समस्या का अंत : 'देश में 1960 के दशक के उत्तरार्ध से शुरू हुआ यह हिंसक आंदोलन एक समय देश के 10 से अधिक राज्यों के 120 से ज्यादा जिलों में फैल चुका था। लेकिन नीतिगत रणनीतियों, आक्रामक अभियानों और 'लोन वर्राटू' (घर वापस आइए) जैसे अभियानों की बदौलत हिंसक वारदातों में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जो आज 31 मार्च 2026 को शून्य पर पहुंच कर इतिहास बन गई।'

31 मार्च क्लोजिंग विशेष: नए लेबर कोड और टैक्स नियमों के कारण आज से घट जाएगी कर्मचारियों की 'टेक होम सैलरी'

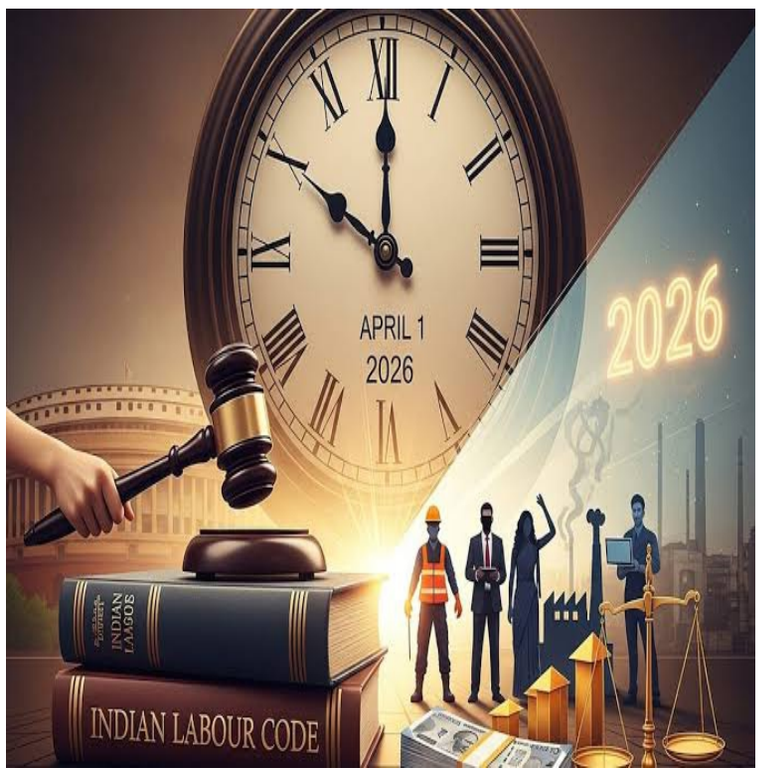

बिजनेस ब्यूरो, नई दिल्ली (31 मार्च)। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष (2026–27) में नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्लिप पूरी तरह बदलने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च की रात को नए लेबर कोड की नियमावली को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी गई है। इस नए नियम के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों की 'बेसिक सैलरी' (मूल वेतन) को उनके कुल पैकेज का कम से कम 50 प्रतिशत रखना अनिवार्य होगा। इसका सीधा असर यह होगा कि कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। इसके कारण 1 अप्रैल के बाद मिलने वाली मासिक इन-हैंड सैलरी में थोड़ी कटौती जरूर दिखेगी, लेकिन रिटायरमेंट के समय मिलने वाला फंड काफी मजबूत हो जाएगा।

मियामी ओपन टेनिस 2026:
रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

मियामी (31 मार्च): भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डेन ने मंगलवार को शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मियामी ओपन मास्टर 1000 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने प्री-क्वार्टर फाइनल के कड़े मुकाबले में सीधे सेटों में 7–5, 7–6 से जीत दर्ज की।

पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटे भारतीय मुक्केबाजय जर्मनी के आमंत्रण टूर्नामेंट में जीते 3 स्वर्ण

बर्लिन (31 मार्च)। आगामी ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुक्केबाजी दल ने जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण मुक्केबाजी टूर्नामेंट में मंगलवार को शानदार प्रदर्शन किया। भारत के तीन मुक्केबाजों (दो पुरुष और एक महिला) ने अपने-अपने भार वर्ग के फाइनल मुकाबलों में विरोधी मुक्केबाजों को सर्वसम्मत फैसले (5–0) से हराकर देश के लिए 3 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले।

महासंकट: कुवैत एयरपोर्ट के ऑयल डिपो पर ईरानी ड्रोन हमलाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर धूं-धूं कर जला, वैश्विक उड़ानों और समुद्री व्यापार पर ब्रेक

संवाद न्यूज एजेंसी

कुवैत सिटी/वाशिंगटन (31 मार्च) : अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा सैन्य युद्ध मंगलवार को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होकर पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया है। मंगलवार की देर रात ईरान की ओर से दागे गए कई आत्मघाती ड्रोनों ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य ईंधन डिपो (ऑयल डिपो) पर हमला कर दिया, जिससे वहां भीषण विस्फोटों के साथ आसमान छूती आग की लपटें उठने लगीं। इस हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आनन-फानन में डायवर्ट करना पड़ा है। युद्ध की इस विभीषिका के चलते वैश्विक स्तर पर विमानन सेवाओं और प्रमुख समुद्री व्यापारिक रूटों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है।

रणनीतिक जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में भारी तबाही, व्यापार ठप : कुवैत एयरपोर्ट पर हमले से ठीक

पहले मंगलवार दिन में, दुबई के तट के पास दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक विशालकाय तेल टैंकर 'अल साल्मी' को भी ईरानी ड्रोनों ने निशाना बनाया। टैंकर पर हुए मिसाइल नुमा हमले के बाद उसमें भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स के जहाज जुटे हुए हैं। व्यापारिक विश्लेषकों का कहना है कि इस रूट पर जहाजों के रुकने से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह ध्वस्त हो सकती है।

ईरान का पलटवार: दो और अमेरिकी 'डफ.9 रीपर' जासूसी ड्रोन ढेर : इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अमेरिकी और इजरायली वायुसेना द्वारा तेहरान और ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई बमबारी का जवाब देते हुए ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी वायुसेना के दो और बेहद महंगे व अत्याधुनिक 'डफ.9 रीपर' जासूसी ड्रोनों को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया है। ईरान की इस आक्रामक जवाबी कार्रवाई ने पश्चिमी देशों के सैन्य खेमे में खलबली मचा दी है।

वैश्विक बाजार ध्वस्त, एयरलाइंस कंपनियों में मची अफरा-तफरी : इस अचानक बढ़े युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों ने एडवायजरी जारी कर सभी कमर्शियल उड़ानों को मिडिल-ईस्ट के ऊपर से न निकलने की सख्त हिदायत दी है। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अब लंबे रूट से जाना पड़ रहा है, जिससे हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। पूरी दुनिया के शेयर और कमोडिटी बाजार इस युद्ध की आग से झुलस रहे हैं।

युद्ध का सीधा असर : ''स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। इस मार्ग के असुरक्षित होने और कुवैत के तेल डिपो पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड +100 प्रति बैरल की तरफ बढ़ने लगी हैं, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।''

ईरान की अमेरिका को खुली धमकी 'अब एप्पल, गूगल और मेटा के दफ्तरों को बनाएंगे निशानाष्य वैश्विक तेल और शेयर बाजारों में हाहाकार

संवाद न्यूज एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय डेस्क, वाशिंगटन/तेहरान (31 मार्च): अमेरिका और ईरान के बीच मध्य-पूर्व में जारी सैन्य टकराव मंगलवार को एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के कुलीन सैन्य बल 'ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स' ने एक आधिकारिक और खुली सैन्य चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि अमेरिका ने उनके और शीर्ष नेताओं या ठिकानों को निशाना बनाया, तो वे युद्ध को सीधे अमेरिकी धरती और उनके आर्थिक हितों तक ले जाएंगे। ईरान ने साफ तौर पर एप्पल, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों के वैश्विक दफ्तरों और सर्वरों को तबाह करने की धमकी दी है। इस बड़े खतरे के सामने आने के बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है।

शीर्ष कमांडर तंगसिरी की हत्या का बदला लेने पर आमादा ईरान : यह बेहद आक्रामक धमकी ईरानी नौसेना के शीर्ष कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की एक संदिग्ध ड्रोन हमले में हुई हत्या के ठीक बाद आई है, जिसका आरोप ईरान ने सीधे अमेरिकी खुफिया एजेंसी और उसकी सेना पर लगाया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने तेहरान में कहा कि अमेरिका केवल मिसाइलों के जवाब की उम्मीद न करेय हमारे 'साइबर वॉरियर्स' और 'स्लीपर सेल्स' अमेरिकी तकनीक, संचार व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सिलिकहन वैली के कॉरपोरेट दफ्तरों को पूरी तरह पंगु बनाने के लिए तैयार बैठे हैं।

व्हाइट हाउस अलर्ट पर, टेक कंपनियों के मुख्यालयों के बाहर सेना तैनात : ईरान की इस सीधी धमकी को अमेरिकी प्रशासन बेहद गंभीरता से ले रहा है। पेंटागन के निर्देश पर वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में स्थित टेक दिग्गजों के मुख्यालयों के साथ-साथ दुनिया भर में फैले अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा को 'रेड अलर्ट' पर डाल दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान इन कंपनियों के डेटा सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर 'रैंसमवेयर' या 'डीडीओएस' (क्क्वै) साइबर हमले कर सकता है, जिससे वैश्विक इंटरनेट सेवा बाधित होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

ट्रंप ने दिए वार्ता के संकेत, कलीबाफ के जरिए रास्ता तलाश रहा अमेरिका : इस भयंकर युद्ध की आशंका के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए अप्रत्याशित रूप से नरमी के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मध्य-पूर्व में पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी राजनयिक इस समय ईरान की संसद (मजलिस) के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ के साथ सीधे संवाद के रास्ते तलाश रहे हैं, ताकि कूटनीतिक स्तर पर इस तनाव को कम किया जा सके। हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ किया कि यदि अमेरिकी संपत्तियों पर कोई भी हमला हुआ, तो ईरान को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जो इतिहास ने कभी नहीं देखी।

बाजारों पर असर: 10,000 करोड़ स्वाहा, क्रूड +95 के पार : ष्ईरान की इस धमकी के महज दो घंटे के भीतर अमेरिकी वायदा बाजार और भारतीय शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़े। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4.8प्रतिशत की छलांग लगाकर +95 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले 48 घंटों में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई, तो वैश्विक मंदी तय है।

पंजाब में टैक्स बकाए के निपटारे के लिए 'वन-टाइम सेटलमेंट' योजना की मियाद समाप्तय आखिरी दिन दफ्तरों में उमड़ी व्यापारियों की भारी भीड़

बिजनेस ब्यूरो, जालंधर (31 मार्च)। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं को प्री-जीएसटी (वैट) के पुराने विवादित मामलों से राहत देने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी 'वन-टाइम सेटलमेंट' योजना की बढ़ाई गई समय-सीमा मंगलवार की रात को समाप्त हो गई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस संबंध में विस्तृत आंकड़े जारी करते हुए बताया कि राज्य के टैक्सपेयर्स, विभिन्न व्यापारिक संगठनों और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की पुरजोर मांग पर इस योजना को मार्च के अंत तक के लिए विस्तार दिया गया था, जिसका राज्य के व्यापार जगत ने भरपूर स्वागत किया है।

करोड़ों रुपये के लंबित टैक्स विवादों का हुआ स्थायी निपटारा : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक, इस योजना के तहत सरकार ने छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को दंडात्मक ब्याज और जुर्माने से बड़ी राहत दी थी। अब तक राज्य भर से 6,348 से अधिक आवेदन आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए जा चुके हैं, जिसके जरिए पिछले कई वर्षों से लटके करोड़ों रुपये के टैक्स विवादों का सौहार्दपूर्ण और स्थायी निपटारा कर दिया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से जहाँ व्यापारियों को कानूनी मुकदमेबाजी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिली है, वहीं पंजाब सरकार के खजाने में भी अच्छा-खासा राजस्व जमा हुआ है।

आखरी दिन सर्वर ने बढ़ाई धड़कनें, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें : मंगलवार को योजना का आखिरी दिन होने के कारण पंजाब के सभी प्रमुख औद्योगिक शहरों (लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बठिंडा) के आबकारी व कराधान कार्यालयों में सुबह से ही व्यापारियों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भारी भीड़ देखी गई। दोपहर के समय अचानक आबकारी विभाग का ऑनलाइन पोर्टल और सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदकों की धड़कनें बढ़ गईं और दफ्तरों में हल्का हंगामा भी हुआ। स्थिति को संभालते हुए विभाग के आला अधिकारियों ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और काउंटरों का समय बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसके बाद रात 8:00 बजे तक फाइलों को जमा करने का काम सुचारू रूप से चलता रहा।

व्यापारियों की मांग: अब 10 हजार तक के छोटे वैट असेसमेंट को बिना शर्त माफ करे सरकार : योजना की मियाद खत्म होने के साथ ही 'पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल' ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। हालांकि, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से अपील की है कि जिन छोटे दुकानदारों के 10,000 या उससे कम के बेहद मामूली वैट केस लंबित हैं, उन्हें बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे कंप्यूटर सिस्टम से ही 'जीरो' (माफ) कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे हजारों छोटे मामलों के चक्कर में विभाग का कागजी बोझ और प्रशासनिक खर्च बेवजह बढ़ रहा है।

क्या थी ओटीएस योजना? : 'इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक के टैक्स बकाए वाले व्यापारियों को ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी गई थी। वहीं, 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के टैक्स असेसमेंट वाले मामलों में ब्याज पर 100प्रतिशत और जुर्माने पर 50प्रतिशत तक की बड़ी राहत दी गई थी, जिसने पंजाब के डूबे हुए टैक्स को रिकवर करने में संजीवनी का काम किया।'

मूकदर्शक समाज और खिड़कियों से झांकती इंसानियत

ऋषि नगर के इस खूनी तांडव ने जहाँ पुलिस की नाकामी को उजागर किया, वहीं हमारे समाज के खोखलेपन को भी बेनकाब कर दिया। बीच सड़क पर आधे घंटे तक एक परिवार को काटा और पीटा जाता रहा, गोलियां चलती रहीं, महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों की छतों, बाल्कनियों और खिड़कियों से तमाशा देखते रहे। किसी एक पड़ोसी ने भी आगे बढ़कर अपराधियों को रोकने या बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई।

यह तमाशबीन मानसिकता अपराधियों के हौसले को दोगुनी ताकत देती है। आज पढ़े-लिखे पहश इलाकों में पड़ोस-धर्म पूरी तरह दम तोड़ चुका है। ऋषि नगर के लोगों को यह सोचना होगा कि आज अगर वे किसी दूसरे के परिवार पर हो रहे अत्याचार को तमाशा समझकर खिड़कियों से देख रहे हैं, तो कल जब उनके अपने घर के बाहर ऐसी विपत्ति आएगी, तो कोई उनकी मदद के लिए भी आगे नहीं आएगा। समाज की यह चुप्पी कायरता की निशानी है।

कमल पवार

हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियाँ: विकास की राह में सबसे बड़ी परीक्षा

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मेहनतकश लोगों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन पहाड़ों की इस खूबसूरती के पीछे कई ऐसी चुनौतियाँ भी छिपी हैं जो आम नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षाकृये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिन पर किसी भी राज्य के विकास की नींव टिकी होती है। यदि इनमें कमजोरी हो, तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है।

सड़कें: विकास की पहली शर्त

हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप कठिन है। बरसात के मौसम में भूस्खलन, सड़क धंसना और पुलों का क्षतिग्रस्त होना आम बात है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क संपर्क सीमित है। इसका असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, पर्यटन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ता है।

सड़कें केवल डामर की परत नहीं होतीं, बल्कि वे विकास की जीवनरेखा होती हैं। समय पर रखरखाव, वैज्ञानिक निर्माण और आधुनिक तकनीक का उपयोग अब आवश्यकता बन चुका है।

स्वास्थ्य: हर गांव तक पहुंचे बेहतर इलाज

हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन दूरदराज क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ की कमी अब भी महसूस की जाती है। कई मरीजों को उपचार के लिए जिला या राज्य मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाए, टेलीमेडिसिन का विस्तार हो और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, तो ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।

शिक्षा: गुणवत्ता पर देना होगा विशेष ध्यान

राज्य की साक्षरता दर देश में बेहतर मानी जाती है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, विज्ञान प्रयोगशालाओं और डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच अभी भी चुनौती बनी हुई है। कई ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी और छात्रों के पलायन की समस्या भी सामने आती है।

आज आवश्यकता केवल स्कूल खोलने की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की है जो विद्यार्थियों को रोजगार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके।

समाधान की दिशा

हिमाचल के विकास के लिए योजनाओं के साथ-साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञता और शिक्षा में आधुनिकता। इन तीनों पर समान रूप से ध्यान देना होगा। सरकार, प्रशासन और समाज सभी की साझी जिम्मेदारी है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

न्यूज एडिटर की कलम से

हिमाचल की पहचान केवल उसकी वादियों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर से भी बनती है। जब गांव तक सुरक्षित सड़क पहुंचेगी, हर नागरिक को समय पर उपचार मिलेगा और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तभी विकास का वास्तविक अर्थ साकार होगा। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति, पारदर्शी नीति और जनसहभागिता से इन्हें अवसर में बदला जा सकता है। यही समय है कि विकास के इन तीन मूल आधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक सक्षम और समृद्ध हिमाचल मिल सके।

अभिषेक न्यूज एडिटर जीत समाचार

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर (भारत)

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)

112	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)	104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Health Helpline/Medical Advice)
100	पुलिस (Police)	1915	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
101	फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)	1930	साइबर अपराध (Cyber Crime)
102 / 108	एम्बुलेंस सेवा (Ambulance)	139	रेलवे पूछताछ / सुरक्षा (Railway Enquiry / Security)
1091	महिला हेल्पलाइन (Women Helpline)	1363	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
1098	चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline)	1033	सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकाल (Road Accident / National Highway Emergency)
		14567	बुजुर्ग हेल्पलाइन (Elder Line)
		1551	किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center)
		1906	गैस सिलेंडर (LPG) रिसाव या आपातकाल (LPG Gas Leak / Emergency)

2. राज्य / बिजली बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)

राज्य	हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)	वैकल्पिक संपर्क नंबर / वैबसाइट
हिमाचल प्रदेश (HPSEBL)	1912	1800-180-8060 | www.hpseb.in
उत्तर प्रदेश (UPPCL / अन्य)	1912	1800-180-8752 | www.uppcl.org
दिल्ली (BSES/TPDDL)	1912	वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट सपोर्ट www.bsesdelhi.com / www.tatapower-ddl.com
पंजाब (PSPCL)	1912	1800-180-1512 | www.pspcl.in
हरियाणा (DHBVN/UHBVN)	1912	1800-180-1833 | www.dhbvn.org.in / www.uhbvn.com
मध्य प्रदेश (MPPKVVCL)	1912	1800-233-1266, WhatsApp: 9425807257 www.mpez.co.in
उत्तराखंड (UPCL)	1912	1800-419-0405 | www.upcl.org

3. राज्यवार जल हेल्पलाइन नंबर

राज्य / विभाग	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / वेबसाइट
केंद्रीय / राष्ट्रीय	1800-121-2164	जल जीवन मिशन का टोल-फ्री नंबर | www.jaljeevanmission.gov.in
हिमाचल प्रदेश (स्थानीय)	1800-180-8009, 1100	जल शक्ति विभाग (SNK), शिकायत निवारण केंद्र
दिल्ली	1916	दिल्ली जल बोर्ड (24x7) | www.delhijalboard.nic.in
उत्तर प्रदेश	1076	सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) | www.up.gov.in
बिहार	1800-123-1121	पीएचईडी (PHED) पेयजल शिकायत | www.prdbihar.gov.in
राजस्थान	1800-180-6088	जलदाय विभाग (PHED) | www.jalday.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सभी राज्य)	181 या 1902	सभी राज्यों की शिकायत और जानकारी के लिए

4. राज्यवार परिवहन (बस) हेल्पलाइन नंबर

राज्य / निगम	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / उपयोग
हिमाचल प्रदेश (HRTC)	1100, 1800 180 8185	24/7 हेल्पलाइन, पूछताछ और शिकायत निवारण
दिल्ली (DTC)	011-22968836	आईएसबीटी (ISBT) पूछताछ
उत्तर प्रदेश (UPSRTC)	149, 1800 1800 151	24/7 टोल-फ्री सुविधा
राजस्थान (RSRTC)	181	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता
चंडीगढ़ (CTU)	1800 274 7400	टोल फ्री नंबर

इन हेल्पलाइन नंबरों को सेव करें और जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची ख़बर की

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।

सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होगे।

R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106

Contact us :- +91-98030-25111.

मुख्यमंत्री का सख्त आदेश: नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों के लाइसेंस होंगे तुरंत रद्द

राष्ट्रीय ब्यूरो, पंचकुला/गुरुग्राम (31 मार्च)। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से पूरे राज्य में बिना मंजूरी के चलने वाले अहातों और सभी प्रकार के कमर्शियल हुक्का बारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 31 मार्च की रात इस मियाद का आखिरी समय होने के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने भारी नाकेबंदी और छापेमारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 अप्रैल की सुबह के बाद किसी भी शराब ठेके के पास अवैध रूप से लोग पीते पाए गए या किसी पब-लाउन्ज में निकोटिन युक्त हुक्का परोसा गया, तो भारी जुर्माने के साथ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।

हरियाणा के किसानों के लिए राहत: मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल अपडेट

कृषि ब्यूरो, करनाल (31 मार्च)। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य की सभी अनाज मंडियों में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधिकारिक खरीद शुरू करने की सभी तैयारियां 31 मार्च की शाम तक पूरी कर ली हैं। इस बार किसानों के खातों में फसल का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के भीतर ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा गया है।

'जीत समाचार' एक्सक्लूसिवः पंजाब के टोल प्लाजा पर आधी रात से बढ़ा टैक्स, पर 'फास्टैग' के वीआईपी वॉलेट से कटेगा अतिरिक्त 'सरचार्ज'- एनएचएआई की छिपी शर्त आई सामने!

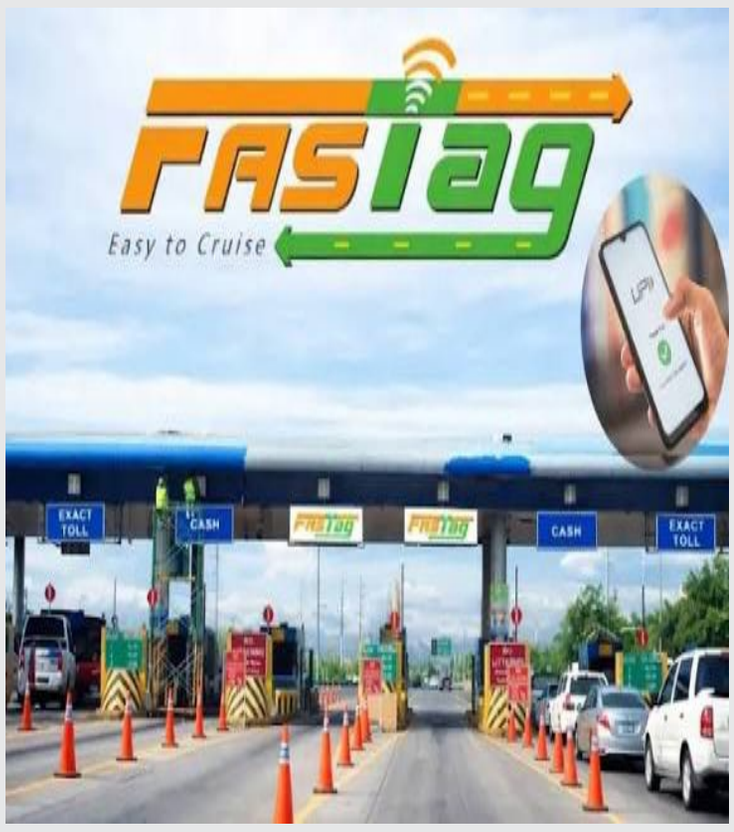

विशेष खोजी ब्यूरो, चंडीगढ़ (31 मार्च)। नए वित्तीय वर्ष (2026–27) की शुरुआत के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पंजाब की जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका दे दिया है। 31 मार्च की आधी रात (12 बजे) से राज्य के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा (लुधियाना) और ट्राईसिटी (चंडीगढ़-मोहाली) को जोड़ने वाले सभी मुख्य टोल नाकों पर बढ़ी हुई दरें प्रभावी रूप से लागू कर दी गई हैं। इस आदेश के तहत निजी कारों से लेकर भारी कमर्शियल वाहनों के लिए प्रति फेरा 5 से 20 तक का इजाफा किया गया है।

लेकिन 'जीत समाचार' की खोजी पड़ताल में एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है जो छप्प की इस नई सूची के बारीक अक्षरों में छिपा था और किसी अन्य मीडिया हाउस ने इसे नहीं देखा।

नया नियमः जीरो बैलेंस या थर्ड-पार्टी फास्टैग वॉलेट पर लगेगा 'मेंटेनेंस पेनल्टी' : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणके इस नए सर्कुलर के अंदरूनी क्लहज के मुताबिक, अब यदि आपके पास नेशनल हाईवे अथहरिटी या सरकारी बैंकों के अलावा किसी प्राइवेट डिजिटल वॉलेट कंपनी (जैसे पेटीएम, फोनपे या अन्य थर्ड-पार्टी ऐप्स) का फास्टैग है, तो हर टोल ट्रांजैक्शन पर 1.50 से 2.50 तक का अतिरिक्त 'प्रोसेसिंग सरचार्ज' ऑटो-डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा, रोजाना सफर करने वाले स्थानीय यात्रियों के लिए जो मासिक पास की सुविधा थी, उसकी मूल कीमत बढ़ाने के साथ-साथ अब पहली बार 18 प्रतिशत का अतिरिक्त 'सर्विस सेस' जोड़ दिया गया है, जिससे मासिक पास की जेब पर पड़ने वाली मार दोगुनी हो गई है।

टैक्सी यूनियनों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों ने खोला मोर्चाय फल-सब्जियां होंगी महंगी : इस गुप्त बढ़ोतरी और अचानक बढ़े टोल टैक्स के विरोध में चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर की कमर्शियल टैक्सी यूनियनों के साथ-साथ 'पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि लाडोवाल जैसे बड़े टोल पर सिंगल जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों ही महंगी होने के कारण जालंधर-लुधियाना रूट पर माल ढुलाई का खर्च प्रति चक्कर 150 से 200 तक बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह से ही पंजाब की मंडियों में आने वाली बाहरी फल और सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार हैं।

टोल काउंटर्स पर बढ़े सुरक्षा बल, आज दोपहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी : अचानक हुई इस बढ़ोतरी के कारण रात 12 बजे के बाद टोल प्लाजा पर वाहन चालकों और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विवाद की स्थिति और हंगामे की आशंका को देखते हुए लाडोवाल टोल प्लाजा और चंडीगढ़-जीरकपुर बैरियर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय किसान संघों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अन्यायी टैक्स बढ़ोतरी और सर्विस सेस को 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया, तो बुधवार दोपहर 1:00 बजे से लाडोवाल टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर इसे पूरी तरह 'टोल-फ्री' करवा दिया जाएगा।

'जीत समाचार' की तीखी टिप्पणी : सड़कें वही हैं, जिन पर गड्ढे और पैचवर्क साफ दिखाई देते हैंय लेकिन हर साल 1 अप्रैल को केवल टैक्स की रसीदें चमका दी जाती हैं। सरकार डिजिटल इंडिया और फास्टैग के जरिए पारदर्शिता का दावा तो करती है, लेकिन कतारों में लगने वाले समय को कम किए बिना जनता की जेब से चुपचाप पैसे निकालने की यह नीति सरासर गलत है।

'जीत समाचार' एक्सक्लूसिवः न्यू चंडीगढ़ के 1,932 करोड़ के मुआवजा अवार्ड के पीछे का सचय 'स्मार्ट-टाउनशिप' की आड़ में कंक्रीट का जंगल बनने की राह पर मुल्लांपुर!

जीत समाचार विशेष खोजी ब्यूरो, चंडीगढ़ (31 मार्च)। पंजाब सरकार द्वारा मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर गरीबदास) के लिए घोषित 1,932.38 करोड़ का मुआवजा अवार्ड जितना बड़ा कृषि जगत के लिए दिख रहा है, उसके पीछे का भविष्य उतना ही चिंताजनक है। 'जीत समाचार' की विशेष पड़ताल में यह साफ हुआ है कि सरकार जिस 309.30 एकड़ जमीन पर पुराने चंडीगढ़ की तर्ज पर 'लो-डेंसिटी' लग्जरी टाउनशिप (बड़ी कोठियां और फार्महाउस) बनाने का दावा कर रही है, वह वास्तव में ट्राईसिटी के रियल एस्टेट में एक नया 'पूंजीवादी एकाधिकार' खड़ा करने की तैयारी है।

इस मेगा प्रोजेक्ट के आने से जहाँ एक तरफ जमीन देने वाले चंद बड़े जमींदार रातों-रात करोड़पति (प्रति एकड़ 6.24 करोड़) बन जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यू चंडीगढ़ का पूरा भूगोल और पर्यावरण हमेशा के लिए बदलने जा रहा है।

पहला बड़ा खतराः शिवालिक की तलहटी का प्राकृतिक जल प्रवाह रुकेगा : पर्यावरण विशेषज्ञों और ट्राईसिटी डेवलपमेंट वाचडॉग से जुड़े इंजीनियरों ने 'जीत समाचार' से बातचीत में इस प्रोजेक्ट पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। मुल्लांपुर का यह पूरा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल करीब है और यहाँ का प्राकृतिक ढलान चंडीगढ़ और मोहाली के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। 309 एकड़ की इस हरी-भरी पट्टी पर जब कंक्रीट की सड़कें, सीवरेज लाइनें और विशालकाय वीआईपी बंगले तनेगे, तो प्राकृतिक जल निकासी पूरी तरह ब्लहक हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में यह न्यू चंडीगढ़ में बाढ़ और पुराने चंडीगढ़ में सूखे का कारण बन सकता है।

जमीन गमाडा की, मुनाफा काटेंगे कहर्पोरेट बिल्डर्स? : अखबारों में यह खबर तैर रही है कि यह गमाडा का सरकारी प्रोजेक्ट है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की मानें तो गमाडा केवल जमीन का अधिग्रहण करके बुनियादी ढांचा (सड़क और बिजली) तैयार करेगा। इसके बाद इन 1–1 एकड़ के लग्जरी प्लहट्स की नीलामी कहर्पोरेट घरानों और बड़े प्राइवेट बिल्डर्स को की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो, सरकार जनता के टैक्स के पैसे (1,932 करोड़) से जमीन खरीदकर, उसे बड़े उद्योगपतियों को री-सेल करने का एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर रही है। इसमें आम या मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा इंसान के लिए 100 या 150 गज के छोटे प्लहट का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है।

लो-डेंसिटी के नाम पर 'हाई-प्रोफाइल' वीआईपी कल्चर को बढ़ावा : प्रशासन का दावा है कि यहाँ 'लो-डेंसिटी' (कम आबादी वाला क्षेत्र) टाउनशिप बनेगी ताकि हरियाली बची रहे। लेकिन सच यह है कि इस नियम की आड़ में यहाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के रसूखदार राजनेताओं, नौकरशाहों और बड़े व्यापारियों के लिए शरिफ्यूज कैंपश (फार्महाउस एस्टेट) तैयार हो रहा है। आम जनता के लिए जो पीआर-8 और पीआर-11 जैसी मुख्य सड़कें जोड़ी जा रही हैं, वे वास्तव में इन वीआईपी फार्महाउसों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट और मुख्य शहर से सीधे जोड़ने का कॉरिडोर मात्र हैं।

4 साल का 'सहूलियत सर्टिफिकेट': पंजाब में जमीनों के दाम आसमान पर जाने तय : सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए सहूलियत सर्टिफिकेट (जिसके तहत नई जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगती) की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है। इसका एक खतरनाक आर्थिक पहलू यह है कि इस 1,932 करोड़ की भारी नकदी के साथ जब न्यू चंडीगढ़ के किसान पंजाब के अंदरूनी जिलों (रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और लुधियाना) में कृषि भूमि खरीदने उतरेंगे, तो वहां की जमीनों के दाम कृत्रिम रूप से आसमान छूने लगेंगे। इससे उन जिलों के स्थानीय छोटे किसानों के लिए जमीन खरीदना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा।

'जीत समाचार' का तीखा सवाल : विकास के नाम पर 1,932 करोड़ का यह मुआवजा पैकेज पहली नजर में मास्टरस्ट्रोक दिखता है। लेकिन क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि इस अधिग्रहण के बाद न्यू चंडीगढ़ आम जनता के रहने लायक रहेगा? या फिर यह इलाका सिर्फ अमीरों का एक ऐसा टाउनशिप बनकर रह जाएगा, जहां की सड़कों पर आम आदमी का प्रवेश भी वर्जित होगा?

शर्मनाकः लुधियाना के निजी अस्पताल ने 2.5 लाख के बकाया बिल के लिए 14 घंटे रोका युवक का शव, मानवाधिकार आयोग सख्त

विशेष क्राइम रिपोर्टर, लुधियाना (31 मार्च)। महानगर के फिरोजपुर रोड स्थित एक नामी निजी अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं और चिकित्सा नैतिकता को पूरी तरह तार-तार करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 31 वर्षीय गगनदीप सिंह का शव महज 2,52,000 के बकाया बिल का भुगतान न होने के कारण रोक लिया। रोते-बिलखते परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के आगे हाथ-पैर जोड़े, लेकिन पत्थरीले दिल वाले प्रबंधन ने साफ कह दिया कि 'जब तक पूरा पैसा काउंटर पर जमा नहीं होता, लाश को मर्चुरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा।' मामले की भनक लगते ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर के बाहर रात भर जोरदार प्रदर्शन किया।

तीन दिन पहले हुआ था दाखिल, इलाज में लापरवाही का भी आरोप : मृतक गगनदीप के पिता कुलवंत सिंह ने रोते हुए बताया कि उनके बेटे को पेट में गंभीर संक्रमण के चलते रविवार को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि दाखिल करते वक्त

1 लाख एडवांस जमा करवाने के बावजूद डॉक्टरों ने इलाज में घोर लापरवाही बरती, जिसके कारण सोमवार रात करीब 11:30 बजे गगनदीप की मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजन शव लेने गए, तो उन्हें 2.5 लाख का एक और अतिरिक्त बिल थमा दिया गया। जब पिता ने असमर्थता जताई, तो अस्पताल के बाउंसरों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और डरा-धमकाकर कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।

मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञानय एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट : इस अमानवीय घटना की गूंज चंडीगढ़ तक पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और बुनियादी मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया है। आयोग ने पंजाब के स्वास्थ्य सेवा निदेशक और लुधियाना के सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डहक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आगामी 7 दिनों के भीतर एक विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का सख्त आदेश दिया गया है।

पुलिस के दखल और हंगामे के बाद आधी रात छूटा शव : मंगलवार दोपहर से शुरू हुआ प्रदर्शन रात होते-होते उग्र हो गया, जिसके बाद इलाके के एसीपी और भारी पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाया, जिसके बाद आखिरकार मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे (करीब 14 घंटे बाद) बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के शव परिजनों को सौंपा जा सका। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर अस्पताल प्रशासन और बाउंसरों के खिलाफ बंधक बनाने और प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्या कहता है कानून? : माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी अस्पताल बिल न चुकाने के एवज में मरीज के शव को बंधक बनाकर नहीं रख सकता। ऐसा करना कानूनन अपराध है और अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का मजबूत आधार है।

31 मार्च क्लोजिंग धमाका: चंडीगढ़ में नए कलेक्टर रेट आज से लागू, ट्राईसिटी में जमीन-जायदाद खरीदना हुआ 15: तक महंगा

जीत समाचार विशेष संवाददाता, चंडीगढ़ (31 मार्च)। चंडीगढ़ प्रशासन ने नए वित्तीय वर्ष (2026–27) की शुरुआत के साथ ही शहरवासियों को बड़ा झटका दिया है। प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से चंडीगढ़ के रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के कलेक्टर रेट में 10 से 15 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। 31 मार्च को पुराने रेट पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए सेक्टर-17 स्थित सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। हालात ऐसे थे कि रात 9 बजे तक रजिस्ट्री का काम चलता रहा। प्रापर्टी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस बढ़ोतरी से ट्राईसिटी (चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला) के रियल एस्टेट बाजार में मंदी का असर देखने को मिल सकता है।

सुखना लेक का जलस्तर बढ़ाय गर्मियों की शुरुआत से पहले प्रशासन ने सिंचाई के लिए पानी छोड़ने पर लगाई रोक

जीत समाचार ब्यूरो, चंडीगढ़ (31 मार्च)। मार्च के अंतिम दिनों में पहाड़ों पर हुई बारिश और बर्फबारी के चलते सुखना लेक के जलस्तर में अप्रत्याशित सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार (31 मार्च) को सिंचाई विभाग और वन विभाग की सांझा बैठक में फैसला लिया गया कि लेक के कैचमेंट एरिया से आने वाले पानी को सुरक्षित रखा जाएगा और गर्मियों के मद्देनजर अगले दो महीनों तक गोल्फ क्लब और अन्य वीआईपी सेक्टर्स के पार्कों की सिंचाई के लिए लेक से पानी नहीं छोड़ा जाएगा।

आईपीएल 2026: मुल्लांपुर में थ्रिलर मुकाबला, पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से रौंदा

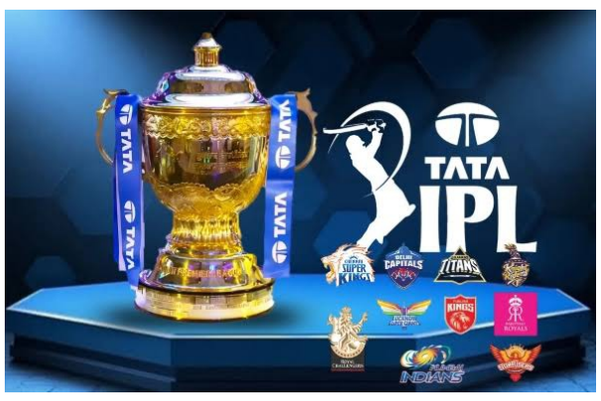

जीत समाचार विशेष खेल संवाददाता, न्यू चंडीगढ़ (31 मार्च)। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार की रात सांसें रोक देने वाले बेहद रोमांचक मुकाबले में घरेलू टीम पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के सामने गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में एक समय पंजाब किंग्स ने अपने शीर्ष बल्लेबाज बेहद सस्ते में गंवा दिए थे, लेकिन मध्यक्रम के अनकैप्ड हीरोज ने मैदान पर ऐसा तूफान लाया कि गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली और 19.5 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

शुरुआती झटकों से उथली थी पंजाब की पारी, फिर हुआ चमत्कार : 200 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम के स्टार ओपनर और कप्तान जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह (35 रन) ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन मध्यक्रम में जितेश शर्मा और सैम करन के भी सस्ते में आउट होने से पंजाब का स्कोर 15.3 ओवर में 150 रन पर 6 विकेट हो गया था। स्टेडियम में बैठे घरेलू दर्शकों की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं और गुजरात की जीत तय लग रही थी।

शशांक का तूफान और आशुतोष का साथरू टूट गया गुजरात का घमंड : यहाँ से मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। क्रीज पर मौजूद शशांक सिंह ने मैदान के चारों तरफ चौकों-छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने महज 29 गेंदों में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 61 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। दूसरे छोर पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए आशुतोष शर्मा ने गुजरात के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर शशांक का बखूबी साथ निभाया। दोनों के बीच महज 23 गेंदों में हुई 43 रनों की साझेदारी ने गुजरात टाइटंस के हाथों से मैच पूरी तरह से छीन लिया। अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर लेग-बाई के जरिए पंजाब ने जीत की दहलीज पार की।

शुभमन गिल की आतिशी पारी गई बेकार : इससे पहले, गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर उनके कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए केवल 48 गेंदों में नाबाद 89 रनों की कप्तानी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 शानदार छक्के जड़े थे। साई सुदर्शन (33 रन) और आखिरी ओवरों में राहुल तेवतिया (23') की तेज बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात ने स्कोर को 199 तक पहुँचाया था। पंजाब की ओर से कगिसो रबाडा ने 44 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हालांकि, शशांक सिंह के आगे गुजरात का यह विशाल स्कोर भी बौना साबित हुआ और शशांक को उनकी अद्भुत पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड । गुजरात टाइटंस: 20 ओवर में 199/4 (शुभमन गिल 89', साई सुदर्शन 33य कगिसो रबाडा 2/44)।

पंजाब किंग्स: 19.5 ओवर में 200/7 (शशांक सिंह 61', आशुतोष शर्मा 31, प्रभसिमरन सिंह 35य नूर अहमद 2/32)

परिणाम: पंजाब किंग्स 3 विकेट से विजयी

ऋषि नगर में खूनी तांडव: सोची-समझी साजिश के तहत 'जीत समाचार' के संपादक कमल पवार पर जानलेवा हमला सिर पर तेजधार हथियारों से वार कर सड़क पर फेंका

जीत समाचार विशेष खोजी ब्यूरो, लुधियाना (31 मार्च)। महानगर के थाना पीएयू के अधीन आते पॉश इलाके ऋषि नगर की गली नंबर-2 में मंगलवार की रात कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द का सरेआम जनाजा निकाल दिया गया। यहाँ 'जीत समाचार' के संपादक कमल पवार (42) को जान से मारने, सरेआम जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने और उनके परिवार को जबरन मोहल्ले से बाहर निकालने (खदेड़ने) की नीयत से एक सुनियोजित खूनी खेल खेला गया। पड़ोसी राजन खन्ना, हरीश खन्ना, उसकी बेटी और दामाद ने पीड़ितों पर हमला करने से पहले उन्हें सरेआम नीचा दिखाने के लिए गंदे जातिसूचक शब्द बोले। इसके बाद उनके द्वारा बुलाए गए मुख्य आरोपी राजविंदर और उसके साथियों ने न केवल अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि संपादक कमल पवार के सिर पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान हालत में अधमरा कर सड़क पर फेंक दिया। इस खूनी तांडव में बीच-बचाव करने उतरे संपादक के जीजा रवि गहलोत की टांग तोड़ दी गई और बहन ममता गहलोत को सड़क पर घसीटकर उनके जेवरात लूट लिए गए।

बोलेरो खड़ी करने का सिर्फ बहाना था, असली मकसद जातिसूचक प्रताड़ना देकर मोहल्ले से निकालना है : 'जीत समाचार' की खोजी पड़ताल में यह साफ हुआ है कि मंगलवार रात को हुआ बोलेरो गाड़ी पार्किंग का विवाद तो महज एक जरिया था, इसके पीछे पड़ोसी राजन खन्ना और हरीश खन्ना का परिवार पिछले लंबे समय से गहलोत परिवार को उनकी जाति को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर वहां से निकालने की साजिश रच रहा था। मंगलवार रात जब कमल पवार अपनी बहन ममता गहलोत और जीजा रवि गहलोत की बोलेरो गाड़ी वापस करने पहुंचे, तो वहां पहले से ही राजन खन्ना के जवाई (दामाद) की गाड़ी आड़ी खड़ी थी। रवि गहलोत ने जब सभ्यता से गाड़ी पीछे करने को कहा, तो राजन खन्ना, हरीश खन्ना, उसकी बेटी और दामाद (जवाई) घर से बाहर आ गए। उन्होंने आते ही पूरे मोहल्ले के सामने कमल पवार और उनके परिवार के लिए अत्यंत अपमानजनक जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और चीखते हुए हंगामा मचाया कि 'इनको सबक सिखाओ, आज इनका काम ही तमाम कर दो, ताकि ये मोहल्ला खाली कर भाग जाएं।'

राजविंदर ने आते ही झोंका फायर, पीड़ितों ने ढूंढा गोली का अहम सबूत : राजन खन्ना और हरीश खन्ना के परिवार द्वारा मचाए गए इस हंगामे के बीच, उनके इशारे पर महज कुछ ही मिनटों में हथियारों से लैस होकर पहुंचे मुख्य हमलावर राजविंदर और उसके साथी ने आते ही अपनी पिस्तौल से सीधे कमल पवार पर गोली चला दी। गोली कमल पवार की दाहिनी बाजू को छूती हुई निकल गई। इसके तुरंत बाद, जब राजविंदर और उसके साथियों ने देखा कि कमल पवार बच गए हैं, तो उन्होंने लोहे की रहड और तेजधार दातर से सीधे कमल पवार के सिर पर बैक-टू- बैक वार कर दिए।

इस भयंकर फायरिंग और अफरा-तफरी के बीच पीड़ित परिवार ने अदम्य साहस का परिचय दिया। गोली चलने के बाद जमीन पर गिरे खाली कारतूस (एम्प्टी शेलध्खोला) को कमल पवार के परिवार और उनके जीजा रवि गहलोत ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित संभाल लिया। हमलावरों की पहचान और उनके अवैध हथियारों को बेनकाब करने के लिए इस सबसे बड़े फहरेंसिक सबूत को आज (बुधवार, 1 अप्रैल) सुबह पीएयू थाना पुलिस के उच्चाधिकारियों को सौंपा जाएगा, ताकि बैलिस्टिक जांच से साफ हो सके कि यह गोली किस पिस्तौल से और किसने चलाई थी।

बहन को सड़क पर घसीटकर लूटे जेवरात, जीजा रवि गहलोत की बेरहमी से तोड़ी लात : जब भाई कमल पवार को मरता देख बहन ममता गहलोत और जीजा रवि गहलोत उन्हें बचाने के लिए चीखते हुए आगे बढ़े, तो आरोपियों ने उन पर पशुओं की तरह हमला कर दिया। हमलावरों ने रवि गहलोत को सड़क पर गिराकर उनके पैर पर भारी रॉड से प्रहार किया, जिससे उनकी लात (टांग) वहीं टूट गई। इसके बाद गुंडागर्दी की सारी हदें पार करते हुए हमलावरों ने ममता गहलोत के बाल पकड़े और उन्हें पत्थरों व कंक्रीट की सड़क पर घसीट-घसीट कर बेरहमी से मारा। इस दौरान हमलावरों ने उनके शरीर पर पहने हुए सोने के कीमती जेवरात भी जबरन खींचकर लूट लिए। खन्ना परिवार के सामने खड़े दूसरे पड़ोसी परिवार ने भी इस पूरी मारपीट में हमलावरों का साथ दिया और पीड़ितों को जमकर पीटा।

लापरवाही की हद: '112' की घंटी बजती रही, मूकदर्शक बने रहे मोहल्ले वाले : इस पूरी वारदात के दौरान पुलिस प्रशासन और समाज दोनों का क्रूर चेहरा सामने आया। हमले के दौरान पीड़ितों द्वारा तत्काल आपातकालीन नंबर '112' पर कहल कर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी पीएयू थाने की पुलिस या कोई पीसीआर वैन मौके पर सहायता के लिए नहीं पहुंची। उधर, ऋषि नगर के लोगों की बुजदिली भी साफ देखने को मिली। बीच सड़क पर आधे घंटे तक एक परिवार को काटा और पीटा जाता रहा, गोलियां चलती रहीं, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों की छतों, बाल्कनियों और खिड़कियों से तमाशा देखते रहे। किसी एक व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर अपराधियों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई।

सिविल अस्पताल में एमएलआर कटवाकर दाखिल हुआ परिवार, एससीध्एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग : पुलिस से कोई मदद न मिलती देख, खून से लथपथ बदहवास हालत में पीड़ित परिवार खुद स्थानीय सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों द्वारा रात में ही कमल पवार, उनकी बहन ममता और जीजा रवि गहलोत की एमएलआर (मेडिको-लीगल रिपोर्ट) काटी गई, जिसके बाद गंभीर चोटों और फ्रैक्चर के कारण तीनों को अस्पताल के स्पेशल वार्ड में दाखिल कर लिया गया। 'जीत समाचार' के संपादकीय बोर्ड और पंजाब के तमाम बड़े पत्रकार संगठनों ने पुलिस कमिश्नर को अल्टीमेटम दिया है कि यदि मुख्य आरोपी राजविंदर, पड़ोसी राजन खन्ना, हरीश खन्ना के परिवार, उनके दामाद, साथ देने वाले सामने वाले परिवार और जेवरात लूटने वाले गुंडों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर धारा 307 (जानलेवा हमला), 392 (लूटना), आर्म्स एक्ट और सख्त एससी/एसटी एक्ट के तहत जेल नहीं भेजा गया, तो पीएयू थाने के बाहर अनिश्चितकालीन चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

'जीत समाचार' का खुला चौलेंज : ''यह हमला सिर्फ कमल पवार पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता, दलित अस्मिता और समाज की सुरक्षा पर हुआ है। सरेआम जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करना और एक सोची-समझी साजिश के तहत परिवार को उजाड़ने और मोहल्ले से निकालने के लिए गुंडे पालने वाले राजन खन्ना और हरीश खन्ना जैसे लोगों को कानून का कड़ा सबक सिखाना बेहद जरूरी है। हमारे पास मौजूद गोली का 'एम्प्टी शेल' (खोला) पुलिस की सुस्त पड़ चुकी तफ्तीश को आईना दिखाने के लिए काफी है।''

कांगड़ा में 2.8 तीव्रता का भूकंप, सुबह-सुबह कांपी धरती

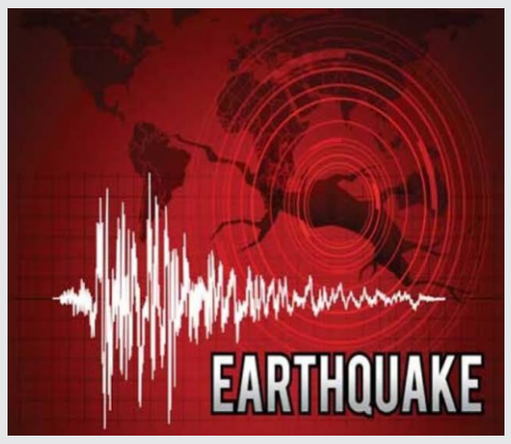

जीत समाचार ब्यूरों कांगड़ा, 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मंगलवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.8 बताई गई। सुबह के समय धरती में कंपन महसूस होने से लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।

भूकंप का झटका हल्की तीव्रता का होने के कारण किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई। कांगड़ा क्षेत्र पहले से ही भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यहां समय-समय पर हल्के भूकंप दर्ज होते रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के रिकॉर्ड में कांगड़ा क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियां दर्ज होती रही हैं।

स्थानीय स्तर पर लोगों ने एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली।

हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 3 से 6 अप्रैल तक बारिश के आसार

जीत समाचार ब्यूरों शिमला, 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के बाद अब अप्रैल की शुरुआत में भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना जताई गई है।

मौसम में बदलाव का असर प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश तथा गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 3 और 4 अप्रैल को पड़ोसी जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार मार्च के अंत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर बना हुआ था। 31 मार्च के आसपास भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की स्थिति बनी रही।

किसानों और बागवानों के लिए सलाहः मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए किसानों और बागवानों को फसलों तथा फलदार पौधों की सुरक्षा के लिए स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से ओलावृष्टि और तेज हवाओं की स्थिति में बागवानी फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ सकता है।

होमगार्ड के 700 पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका

जीत समाचार ब्यूरों शिमला, 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार को महत्वपूर्ण अवसर है। होमगार्ड के 700 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

भर्ती अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी होमगार्ड के पद भरे जाने हैं। विभाग की ओर से जारी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य मापदंडों का पालन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाएगा। इसमें निर्धारित शारीरिक दक्षता एवं अन्य परीक्षणों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता परखी जाएगी। विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण और दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें।

होमगार्ड भर्ती को प्रदेश में नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में सरकारी तंत्र की सहायता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका काफी अहम रहती है।

आवेदकों के लिए जरूरी बातः अंतिम दिन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर अधिक लोड होने की स्थिति से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आवेदन की रसीदधप्रिंट सुरक्षित रखें।

देवता शिखडू महाराज की शोभायात्र से शुरू होगा राज्य स्तरीय रोहडू मेला

"शिखडू महाराज की अगुवाई में सजेगा रोहडू, राज्य स्तरीय मेले में दिखेगी देवभूमि की संस्कृति"

जीत समाचार रोहडू, 31 मार्च 2026। शिमला जिले के रोहडू में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रोहडू मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले का शुभारंभ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देवता शिखडू महाराज की भव्य शोभायात्रा से किया जाएगा। मेले को लेकर प्रशासन और स्थानीय आयोजक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

मेले के दौरान हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और देव परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। शोभायात्रा में पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ स्थानीय लोग और विभिन्न सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। आयोजन में महिला मंडलों की प्रस्तुतियां तथा लोक संस्कृति से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

आयोजन समिति की बैठक में मेले के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

इस बार मेले को नशामुक्त समाज के संदेश से जोड़ने की भी तैयारी है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोहडू मेला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र की देव संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण उत्सव है। हर वर्ष बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक इस आयोजन में शामिल होते हैं।

पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, आरक्षण रोस्टर को लेकर नई अधिसूचना

जीत समाचार शिमला, 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। इससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

नई व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना है। आरक्षण रोस्टर तैयार करते समय संबंधित पंचायतों में विभिन्न वर्गों की आबादी तथा पहले हुए चुनावों में आरक्षण की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। नई अधिसूचना के बाद संबंधित जिला प्रशासन और पंचायती राज अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पंचायत स्तर पर आवश्यक आंकड़े और रिकॉर्ड जुटाकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम किया जाएगा।

राज्य में पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनावों को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांवों में विभिन्न पदों के लिए दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही कई संभावित उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट होगी।

अधिकारियों के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव संबंधी अन्य औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं को भी चरणबद्ध तरीके से अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चलेगी।

एंट्री टैक्स पर सरकार को घेरा, सीमा पर आंदोलन की चेतावनी

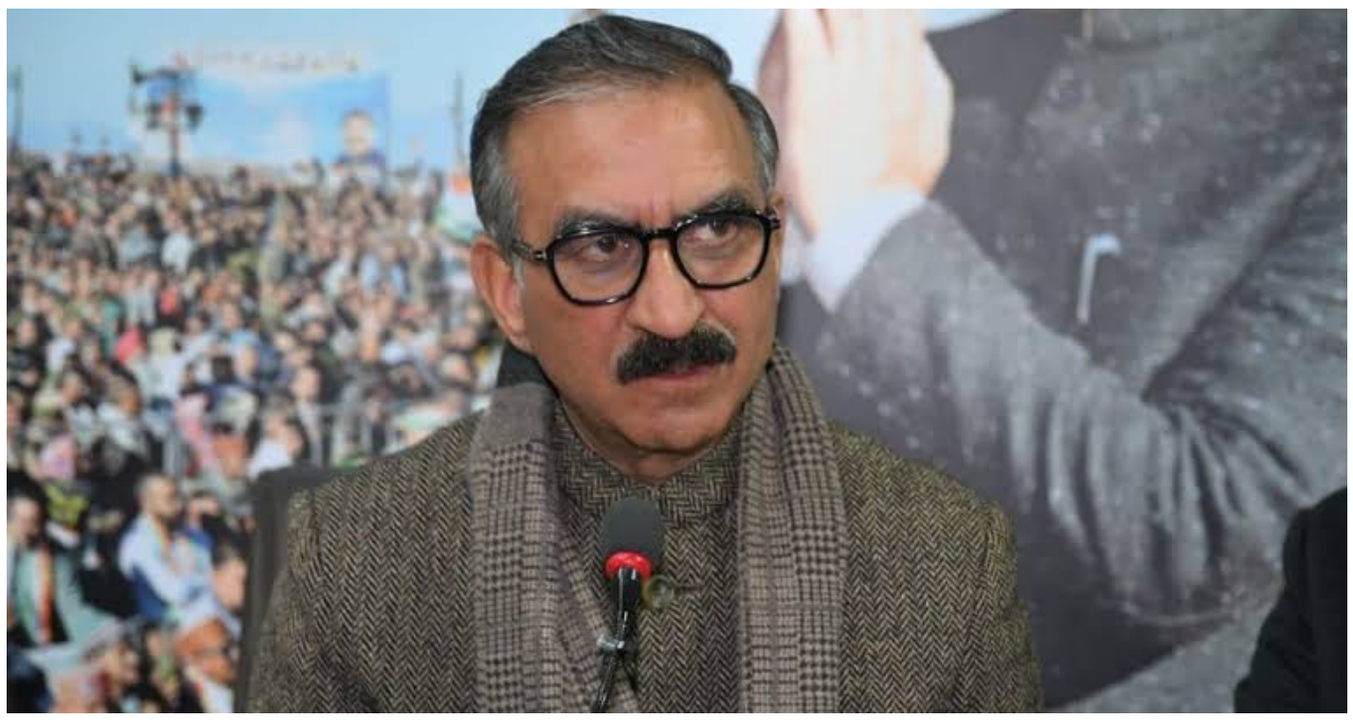

जीत समाचार ब्यूरों शिमला, 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू एंट्री टैक्स को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सियासी माहौल गरमा गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार की नई टैक्स व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे आम लोगों, पर्यटकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त बोझ बताया।

विवाद उस समय और बढ़ गया जब पंजाब और हरियाणा से जुड़े परिवहन संगठनों ने हिमाचल में प्रवेश शुल्क के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। पंजाब के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवहन संगठनों, टैक्सी यूनियनों और अन्य समूहों ने 1 अप्रैल से हिमाचल-पंजाब के बीच वाहनों की आवाजाही रोकने का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों ने सीमा जिलों के लिए एंट्री टैक्स पूरी तरह समाप्त करने तथा अन्य क्षेत्रों के लिए दरों को तर्कसंगत बनाने की मांग की।

विधानसभा में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि एंट्री टैक्स व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने नई दरों में बदलाव करते हुए छोटी यात्री गाड़ियों के लिए राहत देने का फैसला किया। संशोधित व्यवस्था में यात्री वाहनों के लिए दर 130 रुपये से घटाकर 100 रुपये प्रतिदिन किए जाने की जानकारी सामने आई।

सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी राहत देने का प्रावधान किया। टोल बैरियर से पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को सत्यापन के बाद रियायतीध्मुफ्त पास की सुविधा देने की व्यवस्था की गई।

विपक्ष का कहना था कि सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे हिमाचल और पंजाब के बीच आवागमन, पर्यटन तथा व्यापार प्रभावित हो। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि टैक्स व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संग्रह के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।

फिल्मी धमाका: ऑस्कर 2026 की सफलता के बाद एसएस राजामौली ने की नई पैन-इंडिया फिल्म 'गरुड़' की घोषणाय महेश बाबू निभाएंगे मुख्य भूमिका

मनोरंजन ब्यूरो, मुंबई (31 मार्च)। भारतीय सिनेमा को वैश्विक पटल पर चमकाने वाले दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली ने मंगलवार की शाम अपनी अगली महात्वाकांक्षी फिल्म 'गरुड़' का आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए फिल्म के पहले कॉन्सेप्ट पोस्टर ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस पैन-इंडिया फिल्म में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म समीक्षकों के अनुसार, ऑस्कर 2026 में भारतीय सिनेमा की मजबूत उपस्थिति के बाद राजामौली का यह अगला प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिनेमाई मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।

अमेजन के जंगलों में फिल्माए जाएंगे वीएफएक्स (टथ्य) एक्शन सीन्स : प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 800 करोड़ आंका गया है, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। फिल्म की कहानी एक वैश्विक एडवेंचर और प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के ताने-बाने पर आधारित होगी। फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग अफ्रीका और अमेजन के घने जंगलों में की जाएगी। हॉलीवुड के जाने-माने स्टंट डायरेक्टर्स और वीएफएक्स स्टूडियोज को इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है, जिसकी शूटिंग इसी साल मई के अंत से शुरू होने की उम्मीद है।

बॉक्स ऑफिस: रिलीज के चौथे हफ्ते भी थमा नहीं 'सिटाडेल: हनी बन्नी' का जादू, कमाई 350 करोड़ के पार

फिल्मी रिपोर्टर, मुंबई (31 मार्च)। मार्च के शुरुआती हफ्ते में रिलीज हुई वरुण धवन और सामंथा स्टारर एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'सिटाडेल: हनी बन्नी' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा मंगलवार (31 मार्च) को भी कायम रहा। फिल्म ने अपने चौथे मंगलवार को घरेलू बाजार में 4.2 करोड़ की शानदार कमाई के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया है। कम बजट और बेहतरीन माउथ पब्लिसिटी के दम पर यह फिल्म साल 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फिल्म के निर्देशक राज और डीके ने दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसके सीक्वल पर काम शुरू करने के संकेत दिए हैं।

शोक: दिग्गज अभिनेता और थियेटर आर्टिस्ट अलेक पद्मसी के भाई का 88 वर्ष की आयु में निधनय फिल्मी जगत में शोक की लहर

मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांसय बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

विशेष संवाददाता, मुंबई (31 मार्च)। भारतीय थियेटर जगत और सिनेमा के लिए मंगलवार की सुबह एक बेहद दुखद खबर लेकर आई। मशहूर थियेटर पर्सनालिटी स्वर्गीय अलेक पद्मसी के भाई और जाने-माने कला समीक्षक का 88 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर मिलते ही अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह समेत बॉलीवुड और थियेटर जगत के कई बड़े कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय कला का एक अनमोल स्तंभ बताया है।